International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 09 Issue 12 Ser. II ||December, 2020 || PP. 91-94

सतत् विकास के राजनीतिक आयाम – वर्तमान परिपेक्ष्य में

डॉ सुरेंद्र सिह
एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली

सन्दर्भ

सतत् विकास से हमारा अभिप्राय ऐसे विकास से है, जो हमारी भावी पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे। भारतीयों के लिए पर्यावरण संरक्षण, जो सतत् विकास का अभिन्न अंग है, कोई नई अवधारणा नहीं है। भारत में प्रकृति और वन्यजीवों का संरक्षण अगाध आस्था की बात है, जो हमारे दैनिक जीवन में प्रतिबिंबित होता है और पौराणिक गाथाओं, लोककथाओं, धर्मों, कलाओं और संस्कृति में वर्णित है। सतत् विकास सामाजिक–आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सहनशक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती हैं। यह अवधारणा सन 1960 के दशक में विकसित हुई जब लोग औधौगीकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों से अवगत हुए। सतत् विकास का उदभव प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति तथा उसके कारण आर्थिक क्रियाओं तथा उत्पादन प्रणालियों के धीमे होने या उनके बंद होने के भय से हुआ।

यह अवधारणा उत्पादन –प्रणालियों पर नियंत्रण करने वाले कुछ लोगों द्वारा प्रकृति के बहुमूल्य तथा सीमित संसाधनों के लालचपूर्ण दुरूप्रयोग का परिणाम है। सतत विकास कोयला, तेल तथा जल जैसे संसाधनों के दोहन के लिए उत्पादन तकनीकों, औधोगिक प्रक्रियाओं तथा विकास की नीतियों के संबंध में दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत करता है।

सतत् विकास की अवधारणा की शुरूआत सन 1962 में हुई जब वैज्ञानिक रॉकल कारसन ने 'दी साइलेंट स्प्रिंग' नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक ने कीटनाशक डी.डी.टी. के प्रयोग से होने वाले नुकसान की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया1। यह पुस्तक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक पक्षों के मध्य परस्पर संबंधों के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई। सन 1968 में जीव विज्ञान शास्त्री पॉल इहरलिच ने अपनी पुस्तक 'पापुलेशन बम' प्रकाशित की जिसमें उन्होंने मानव जनसंख्या, संसाधन दोहन तथा पर्यावरण के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला। सन 1969 में गैर–सरकारी संख्या फ्रेण्डस ऑफ दी अर्थ बनाई गई जिसे पर्यावरण की रक्षा में नागरिकों को भाग लेने हेतु सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया गया। सन 1971 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ने 'प्रदुषक खर्चा दे' सिद्घांत बनाया जिसमें यह कहा गया कि प्रदूषण फैलाने वाले देशों को उसकी कीमत देनी चाहिए। सन 1972 में मेसाचूसेटस इंस्ट्रीस्यूट ऑफ टेकनोलॉजी से युवा वैज्ञानिकों के एक समूह 'क्लब ऑफ रोम' ने अपनी रिपोर्ट 'लिमिटस टू ग्रोथ' प्रकाशित की जिसने पूरे विश्व में हलचल मचा दी। इस रिपोर्ट में वर्तमान विकास दर को धीमा न करने पर गंभीर परिणामों की भविष्यवाणी की गई।

सन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। पहली बार विश्व समुदाय में इस बात पर सहमति हुई कि पर्यावरण संकट एक गंभीर मुद्धा है। इससे ' संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' की स्थापना हुई। सतत विकास की अवधारणा का विकास सबसे पहले सन 1987 में ब्रंटलैण्ड आयोग की रिपोर्ट 'अवर कॉमन फ्यूचर' के प्रकाशन के साथ हुआ। इसमें सतत विकास को विकास की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा गया जो वर्तमान पीढियों की आवश्यकताओं के साथ–साथ भविष्य की आवश्यकताओं कोभी ध्यान में रखता है।

सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राजील की राजधानी रियो डि जेनीरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। यह पर्यावरण संरक्षण पर अब तक का सबसे बडा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें 182 देशों के 20,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दिसम्बर, 1992 में सतत विकास के काग्रक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास आयोग का गठन किया गया। इसी क्रम में सन 2002 में जोहांसबर्ग में सतत विकास पर विश्व सम्मेलन, सन 2005 में कनाडा के मोंट्रियल शहर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, सन 2006 में ढयूयॉर्क में वनों के सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन तथा दिसम्बर, 2007 में इंडोनेशिया के बाली द्वीप में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन आयोजित किया गया। स्थायी विकास का अभिप्राय आर्थिक विकास के साथ–साथ पर्यावरण को सुरक्षित करना है। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रखना है।सतत विकास के कुछ दूरगामी तथा व्यापक उद्देश्य हैं जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्रीय बंधनों से मुक्त हैं। ये उद्देश्य शोषणकारी मानसिकता की जंजीरों से अर्थव्यवस्था की मुक्तिता हेतु ऐसा अधिकार पक्ष है जिन्होंने राष्ट्रों की जैव संपदा को नष्ट होने से बचाया है सतत विकास एक मूल्य आधारित अवधारणा है, जो परस्पर सह– अस्तित्व तथा सभी के लिए सम्मान जैसे

आदर्शों की मांग करता है। यह एक निरंतर विकास प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा पर्यावरणीय घटकों में सामंजस्य पर आधारित है।

ट्रांस्फॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संकल्प को, जिसे सतत विकास लक्ष्यों के नाम से भी जाना जाता है, भारत सहित 193 देशों ने सितंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में स्वीकार किया गया था और इसे एक जनवरी, 2016 को लागू किया गया। सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सबके लिए समान, न्यायसंगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना और विकास के तीनों पहलुओं, अर्थात सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के बाद,जो सन 2000 से सन 2015 तक के लिए निर्धारित किए गए थे, विकसित इन नए लक्ष्यों का उद्देश्य विकास के अधूरे कार्य को पूरा करना और ऐसे विश्व की संकल्पना को मूर्त रूप देना है, जिसमें कम चुनौतियां और अधिक आशाएं हों। सतत विकास सदैव हमारे दर्शन और विचारधारा का मूल सिद्धांत रहा है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक मोर्चों पर कार्य करते हुए हमें महात्मा गांधी की याद आती है, जिन्होंने हमें चेतावनी दी थी कि धरती प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है, पर प्रत्येक व्यक्ति के लालच को नहीं।

भारत लंबे अरसे से सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और इसके मूलभूत सिद्धांतों को अपनी विभिन्न विकास नीतियों में शामिल करता आ रहा है। हाल के विश्वव्यापी आर्थिक संकट के बावजूद विकास की अच्छी दर बनाए रखने में भारत सफल रहा हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सबसे निर्धन वर्ग के कल्याण को प्रमुखता दी। इसलिए सन 2030 के सतत् विकास एजेंडे में निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य न केवल भारत का नैतिक दायित्व है, बल्कि शांतिपूर्ण, न्यायप्रिय और चिरस्थायी विश्व को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी भी है।

भारत के विकास संबंधी अनेक लक्ष्यों को सतत विकास लक्ष्यों में शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अनेक कार्यक्रम सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जिनमें मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ–बेटी पढाओ, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण और शहरी दोनों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डिजिटल इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शामिल हैं। इसके अलावा अधिक बजट आवंटनों से बुनियादी सुविधाओं के विकास और गरीबी समाप्त करने से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सतत विकास लक्ष्यों को विकास नीतियों में शामिल करने के लिए अनेक मोर्चों पर कार्य किया जा रहा हैं हैं, ताकि पर्यावरण और पृथ्वी के अनुकूल एक बेहतर जीवन जीने की वैध इच्छाओं को पूरा किया जा सके। केंद्र सरकार ने सतत् विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने तथा इसके समन्वय की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को संबंधित राष्ट्रीय संकेतक तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा प्रस्तावित संकेतकों की वैश्विक सूची से उन संकेतकों की पहचान करना, जो राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के लिए अपनाए जा सकते हैं, वास्तव में एक मील का पत्थर है।

संघीय ढांचे में सतत विकास लक्ष्यों की संपूर्ण सफलता में राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यों में विभिन्न राज्य स्तरीय विकास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं का सतत विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को सतत् विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में आनेवाली विभिन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। सतत् विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय संसद विभिन्न हितधारकों के साथ गहन विचार–विमर्श कर रही है। जैसे, अध्यक्षीय शोध कदम (एसआरआई), स्थापित किया गया एक मंच है, सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर हमारे सांसदों द्वारा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श को सुविधाजनक बनाता है। इसके अलावा नीति आयोग ने अन्य संगठनों के सहयोग से विशेष सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर परामर्श शृंखलाएं आयोजित की हैं, ताकि विशेषज्ञों, विद्वानों, संस्थाओं, सिविल सोसाइटियों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और केंद्रीय मंत्रालयों सहित राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ गहन विचार–विमर्श किया जा सके।

भारत सरकार द्वारा, न्यूयार्क में जुलाई, 2017 में आयोजित होने वाले उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ) पर अपनी पहली स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) प्रस्तुत करने हेतु लिया गया निर्णय इसका उदाहरण है कि भारत सतत विकास लक्ष्यों के सफल कार्यान्वयन को कितना महत्व दे रहा है। पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए संपूर्ण विकास हेतु लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य तथा स्थानीय स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति और संस्था द्वारा और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

विकासशील देश आज व्यापक गरीबी, भूख और आय असमानता के विशेष संदर्भ में सतत विकास के तीनों आयामों–आर्थिक, सामाजिक और ग्लोबल वार्मिंग संबंधी मुश्किलों और चुनौतियों को झेल रहे हैं। इन देशों के लिये

प्राथमिक शिक्षा, जन स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, महिला आधिकारिता को बढ़ावा देना और विकास के लिये वैश्विक साझेदारी विकसित करना एक महत्वपूर्ण आयाम है।

सन 2001 में जब गोल्डमेन सेच्स के भूतपूर्व चेयरमेन जिम ओ'नील ने ब्रिक नाम दिया था तो इसमें चार देश ब्राजील, रूस, भारत और चीन ही सदस्य थे। जिम ने अपने एक प्रकाशन "बिल्डिंग ग्लोबल इकोनामिक" में ब्रिक का उल्लेख किया था। सितम्बर 2006 में ये चार देश संयुक्त राष्ट्र की जनरल एसेम्बली में मिले और जून 16, 2009 को रूस के येकर्टिंबर्ग में इन देशों की पहली बैठक हुई थी। सन 2010 में जब ब्राजील में ब्रिक देश मिले तो उसमें साउथ अफ्रीका इन देशों के संगठन से आ मिला तो इसका नाम "ब्रिक्स" हुआ। ब्रिक्स का मूल उद्देश्य है–पांचों देशों के बीच व्यावसायिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग किस तरह से बढ़ाया जाये।

चीन ने सन 2011 में, भारत ने सन 2012, साउथ अफ्रीका ने सन 2013, ब्राजील ने सन 2014 और सन 2015 में रूस ने ब्रिक्स की बैठकें आयोजित की थीं। आगामी बैठक पणजी में आयोजित की गई । ब्रिक्स देशों का अपना नेशनल डेवलेपमेंट बैंक और एक कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट नाम से यूनिट है जो ब्रिक्स के आर्थिक मामले देखती है। विश्व की 43 प्रतिशत जनसंख्या इन ब्रिक्स देशों में और जीडीपी में इन देशों का योगदान 37 प्रतिशत है। चीन के व्यवसाय में 40 प्रतिशत महिला व्यवसायी हैं, ब्राजील में 45 प्रतिशत और भारत में केवल 11 प्रतिशत हैं। ऐसे में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का सवाल प्रासंगिक हो जाता है।

भारत ने ब्रिक्स की सालाना गतिविधियों का एक कैलेंडर बनाया हुआ है, जिसके तहत जयपुर में ब्रिक्स देशों की महिला सांसदों का सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें चार देशों से 14 और भारत से 28 महिला सांसदों ने तीन प्लेनरी सेशंस में भाग लिया। ब्रिक्स ने 19 बिंदुओं का "जयपुर डिक्लेरेशन" जारी किया और संकल्प लिया कि इसे अक्तूबर में गोवा में होने वाले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में प्रस्तुत किया जायेगा। इस रिजोल्यूशन में 2030 ब्रिक्स सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रयासरत है।

राष्ट्रीय हो या वैश्विक स्तर के संगठन या देशों के समूह, आम आदमी की मौलिक समस्याएं हर विकासशील देशों में एक जैसी हैं। इन सब के गर्भ में अशिक्षा और युवा बेरोजगारी प्रमुख है। इन समस्याओं से बचकर सतत् विकास के लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन पर मात्र चर्चा पर चर्चा करना क्या विकासशील देश भारत की जनसंख्या को स्वीकार्य होना चाहिये? दरअसल सात दशक बाद भी चहुंमुखी विकास नहीं हुआ और जो कुछ हुआ, उससे आज भी सतत विकास की प्रकिया से जोड़ने की कवायद की जा रही है। वो भी अपने स्तर पर नहीं बल्कि ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर जो स्वयं की समस्याओं से त्रस्त हैं। भारत सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त करने के मामले में पीछे है। इस सूचकांक में वह 149 देशों में 110वें स्थान पर है जबकि स्वीडन को शीर्ष स्थान हासिल हुआ। सूचकांक से साफ है कि सभी देशों को इन महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के मामले में प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सतत विकास समाधान नेटवर्क (एसडीएसएन) और बर्टल्समैन स्टिफटंग ने नया सतत विकास सूचकांक पेश किया ताकि सतत विकास लक्ष्य की प्रगति का आकलन हो सके और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो। सूचकांक ने 149 देशों के आंकड़ों का संग्रह किया ताकि इसका आकलन हो सके कि सन 2016 में हर देश सतत् विकास लक्ष्य के मामले में कहां खड़े हैं। सूचकांक में विभिन्न देशों के 17 वैश्विक लक्ष्यों के मामले में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी गई है जो सतत् विकास के तीन आयामों– आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरण वहनीयता से जुड़े हैं।

सूचकांक से विभिन्न देशों को जल्द उठाए जाने वाले कदमों की प्राथमिकता की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे साफ होता है कि विभिन्न देशों के सामने सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रमुख चुनौतियां हैं। सूचकांक से देश को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक मार्ग तलाशने में मदद मिल सकती है। जो देश लक्ष्यों को हासिल करने के करीब हैं वे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं नहीं बल्कि अपेक्षाकृत छोटे और विकसित देश हैं। इस सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पर है, जिसके बाद डेनमार्क और नार्वे तीन शीर्ष स्थानों पर हैं। इस सूची में जर्मनी (छठा स्थान) और ब्रिटेन (10वां स्थान) ही सिर्फ ऐसे देश हैं जो शीर्ष 10 में शामिल हैं। अमेरिका सूचकांक में 25वें स्थान पर है जबकि रूस 47वें और चीन 76वें स्थान पर है। भारत 110वें स्थान पर है।

सतत् विकास के उद्देश्यों तथा मूल्यों को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास हुए हैं जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं – स्टॉकहोम सम्मेलन, पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग की स्थापना, पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र, जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा संबंधी अनुबंध, जैव विविधता पर अनुबंध, वन संरक्षण सिद्धान्त, रियो घोषणा, कार्यसूची – 21, सतत विकास पर जोहांसबर्ग सम्मेलन, सुशासन की स्थापना, क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन पर बाली सम्मेलन प्रमुख है। सतत विकास के समक्ष सबसे बडी चुनौती बिना विकास की रफ्तार को रोके पर्यावरण संरक्षण तथा संसाधनों का प्रबंध करना है। यह पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक विकास का मुख्य अंग मानता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य हलों को प्राप्त करने में उत्तर–दक्षिण विभाजन बातचीत के बीच बाधा बनता है। विकासशील देश मानते हैं कि पर्यावरण संबंधी नियमों को लागू कर विकसीत देश उन्हें विकास प्रक्रिया से पिछे धकेल रहे हैं। संसाधनों का अधिकतम उपभोग विकसीत देश करते हैं जबकि गरीब देशों को उपभोग की कीमत प्रदूषण, जैव विविधता हस, जंगलों के कटने तथा प्राकृतिक संसाधनों के शोषण के रूप में चुकानी पड़ती है।

विकसीत देश गरीब देशों से उनके जंगलों तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर प्रतिबंध की बात कर रहे हैं लेकिन वे अपने यहाँ अत्यधिक उत्पादन तथा उपभोगवादी जीवनशैली को बदलने को तैयार नहीं हैं। जलवायु सम्मेलनों अथवा क्योटो प्रावधानों पर भी विकसित तथा विकासशील देश एकमत नहीं हैं। विकासशील देशों का मानना है कि पर्यावरण प्रदूषण का मूल कारण औद्योगिक देशों की अति–उपभोक्तावादी जीवनशैली है इसलिए पर्यावरण संरक्षण अथवा सतत विकास की प्राप्ति के लिए विकसीत देशों द्वारा गरीब देशों को तकनीकि तथा वित्तिय सहायता प्रदान करनी चाहिए। परन्तु इस पर भी पूर्ण सहमति नहीं बनी है। सतत् विकास की अवधारणा को सैद्धान्तिक तौर पर मानना आसान है परन्तु इसको व्यावहारिक रूप में लाना उतना ही कठिन है क्योंकि इसके परिमापों पर सहमति नहीं है। जहाँ राष्ट्रों का हित आर्थिक विकास प्राप्ति में है वहीं वास्तविक चुनौती यह है कि ऐसे विकास का ढांचा खडा किया जाये जो आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बना सके।

एक अवधारणा के रूप में सतत विकास का जन्म सन 1960 के प्रारंभिक वर्षों में हुआ जब विकसीत देशों में अनियंत्रित औधोगिकरण के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। इसको रॉकल कारसन ने अपनी पुस्तक 'साइलेंट स्प्रिग' में स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया है। सन 1987 में ब्रंटलैण्ड आयोग की रिपोर्ट के बाद सतत विकास पर चर्चा आम हो गई है। सतत विकास आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोडता है इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना है। यह चेतावनी देता है कि मनुष्य पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं कर सकता क्योंकि इसमें अंततरू मनुष्य की ही हार है। पृथ्वी की सहनक्षमता के अनुरूप विकास, लैंकिक समानता, सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता सतत विकास के मुख्य सिद्धान्त हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपनी कार्यसूची में पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यह उन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से प्रमाणित होता है जिनमें विश्वभर के राजनीतिक नेताओं ने पर्यावरण–रक्षा के प्रति अपनी चिंता तथा इस दिशा में किए जाने वाले प्रयत्नों के प्रति अपने समर्थन को दोहराया है। पर्यावरण संरक्षण में गैर–सरकारी संगठन भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनके प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण ने एक आंदोलन का रूप ले लिया है। सतत विकास की प्राप्ति में उत्तर–दक्षिण विभाजन एक बडी चुनौती है।

विषय की गंभीरता को देखते हुए आज आवश्यकता है कि विकसीत देश इस दिशा में एक सार्थक भूमिका निभायें। उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि अग्रणी राष्ट्र के रूप में उन्हें एक उदाहरण स्थापित करने की जरूरत है। अंत में सतत् विकास की सबसे बडी चुनौती आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है क्योंकि इसी संतुलन पर मानव का अस्तित्व टिका हुआ है। गरीब और विकासशील देश सतत् विकास सूचकांक में सबसे निचले स्तर पर हैं। यह बात समझी जा सकती है क्योंकि उनके पास अक्सर अपेक्षाकृत कम संसाधन होते हैं। उन्हें अभी भी सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काफी लंबा सफर तय करना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

1. Agrawal, Anil, "What is Sustainable Development a Down to Arth" ,1992, P 50-51
2. Drej & Sen, "India Development and Participation" ,Oxford University Press, New Delhi , 2006, P 218
3. "Our Common Future", World Commission on Environment and Devlopment, Oxford Press, New Delhi, 1987
4. "Political Declaration and Plan of Implementation", Johannesburg Declaration on Sustainable Devlopment, United Nations, 2003, P 12-13
5. Nayar, K R, "Politics of Sustainable Development ",Economic & Political Weekly 1992, Vol. 29, No.22, P 1327
6. Solanki, S A, "The Concept of Sustainable Development Root Conotetions and Critical Evaluation", Social Change, 2003, Vol.33, No.1, P.68
7. चक्रवर्ती, बिधुत, चंद, प्रकाश, " भारतीय प्रशासन विकास एवं पद्धति ", सेज पब्लिकेशन्स इंडिया प्रा लि, नई दिल्ली, 2017
8. सिंह, कटार, शिशोदिया, अनिल, " ग्रामीण विकास सिद्धान्त नीतियां एवं प्रबन्ध ", सेज पब्लिकेशन्स इंडिया प्रा लि, नई दिल्ली, 2018
9. "भारत सतत् विकास सूचकांक में 110वें स्थान पर ", जनसत्ता, 14 मार्च 2018
10. "बाली क्लामेट डील ", हिंदुस्तान टाइम्स, 16 दिसम्बर, 2007, पृ–18
11. गोयल, यश, "विकास में वैश्विक भागीदारी की पहल", दैनिक ट्रिब्यून, 23 अगस्त 2016
12. "सतत् विकास का लक्ष्य और भारत ", अमर उजाला, 15 फरवरी 2017